For Immediate release
February 22, 2013

Eminent educationists across the country have strongly criticised the recent move of the Government of Rajasthan to provide 112,000 laptops to students, pre-loaded with proprietary software applications such as Microsoft Office 2010 Professional and Adobe Acrobat Professional and have written to the Education Minister advising against this move. Dr Vinod Raina, member of the Central Advisory Board of Education, an advisory body to MHRD, said *"The decision of the Rajasthan Government violates the National Policy on ICT in School Education passed by the Central Advisory Board for Education."* The National ICT Policy clearly recommends the use of a wide variety free and open source software applications for its rich learning potential.

These are many high quality FOSS alternatives to the Adobe and Microsoft proprietary applications specified in the bid document, and Gurumurthy Kasinathan, Director of IT for Change said "the government can save anywhere between 50 to 100 crore rupees on this laptop procurement by going for FOSS". The letter points out that large states such as Kerala, Karnataka and Gujarat are using these FOSS applications in their ICT programmes in schools and their benefits have been acknowledged by a CABE sub-committee on ICTs and education. This committee has also pointed to the danger of the "appropriateness of proprietary software in terms of pedagogy, equity and larger public interest... more so because information about these technologies is mostly spread by their vendors, whose major concern, understandably, is to sell them more and more".

The letter states that apart from economic considerations, the use of software that teachers cannot share or modify based on local needs will be educationally inadvisable. Rohit Dhankar, Digantar member of the National Curricular Framework, 2005 focus group, said, 'Imagine a carpenter who cannot sharpen or modify his tools in any way. This person will be totally governed in his work-style and work-habits by the tool manufacturers; and would almost be a slave to their ways of thinking about how carpentry can be done. Anyone using computers on a predetermined set of unchangeable operating systems is likely to be a bigger slave in ways of thinking and using computers as the software developers want him to do. Most of us are slaves of these software companies, and therefore, find it very hard to imagine alternative ways.' The letter also suggests that merely distributing laptops to students is unlikely to have significant benefits in the absence of systemic preparation including teacher training and local infrastructure maintenance.

The bid document of the Rajasthan Government as well as the letter to the Minister are available on http://www.itforchange.net/Letter_Rajasthan_government_Laptop_purchase_feb2013

Neeru Malhotra
09916893596

IT for Change
www.ITforChange.net

तत्काल प्रकाशन के लिए

22 फरवरी, 2013

देश भर के जाने माने शिक्षाविदों ने राजस्थान सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को मालिकाना हक वाले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 प्रोफेशनल और अडोब एक्रोवेट प्रोफशनल जैसे सॉफ्टवेयर से लैस ११२,००० लैपटॉप खरीदने के हाल के निर्णय की दृढता से आलोचना की है और एक पत्र मे शिक्षा मंत्री को ऐसा ना करने की सलाह दी है। टेंडर दस्तावेज में यह उल्लेख किया है कि लैपटॉप Microsoft Office 2010 Professional और Adobe Acrobat Professional जैसे मालिकाना सॉफ्टवेयर के साथ pre-loaded आयेंगे | डॉ. विनोद रैना, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक सलाहकार सदस्य ने कहा, *"राजस्थान सरकार के निर्णय स्कूल शिक्षा में आईसीटी शिक्षा के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा पारित कर दिया पर राष्ट्रीय नीति का उल्लंघन करती* है,"। राष्ट्रीय आईसीटी नीति स्पष्ट रूप से स्वतंत्र और खुले स्रोत सॉफ्टवेयर की क्षमता की वजह से उसके उपयोग की सिफारिश करती है।

खरीद बिड दस्तावेज में निर्दिष्ट Adobe और Microsoft मालिकाना applications जैसे ही उच्च स्तर की applications FOSS मे भी उपलब्ध हैं। गुरुमूर्ति कासिनाथन IT for Change के निदेशक ने कहा, "सरकार FOSS को अपना कर इस टेंडर पर 50 से 100 करोड़ रुपए की बचत कर सकती है"। केरल, कर्नाटक और गुजरात जैसे बड़े राज्यों के स्कूल FOSS applications का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके फायदों को CABE उप समिति द्वारा स्वीकार किया गया है । इस समिति ने मालिकाना सॉफ्टवेयर के खतरों को बताते हुए कहा है, "शिक्षण, समानता और जनता के व्यापक हित में मालिकाना हक वाले इन सॉफ्टवेयर की उपयुक्तता के बारे में ज्यादतर जानकारी इनके विक्रेता ही प्रसारित करते हैं, और उनका मुख्य सरोकार अपने सॉफ्टवेयर को अधिक से अधिक बेचना होता है।"

पत्र में कहा गया है कि आर्थिक आधार के अलावा, अगर सॉफ्टवेयर स्थानीय जरूरतों पर आधारित नहीं हैं तो उसका उपयोग शैक्षिक रूप से अनुचित होगा। रोहित धनकर, दिगन्तर्, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की संचालन समिति के सदस्य ने कहा, "कल्पना कीजिए एक बढ़ई जो अपने औजारों की धार तेज नहीं कर सकता और उन्हें बदल नहीं सकता। काम करने की शैली और आदतों में इस व्यक्ति को पूरी तरह से औजार निर्माताओं से संचालित होना होगा और बढईगिरी कैसे की जा सकती है इस बारे में निमार्ताओं के सोचने के तरीकों का गुलाम होना होगा। किसी के द्वारा पहले से तय ऑपरेटिंग सिस्टम के सेट पर बिना बदलाव के काम करना सॉफ्टवेयर निर्माताओं के सोचने के तरीकों और कम्प्यूटर का उपयोग सॉफ्टवेयर निर्माताओं के चहेते बडे गुलाम की तरह है। हममें से अधिकांश इन सॉफ्टवेयर कंपनियों के दास हैं, और इसलिए, वैकल्पिक तरीके की कल्पना करना बहुत मुश्किल हे |" पत्र में यह भी कहा गया है कि केवल छात्रों को लैपटॉप बांट देने से प्रणालीगत तैयारी के अभाव में लाभ की संभावना नहीं है |

राजस्थान सरकार के बिड दस्तावेज और मंत्री को पत्र यहां पर उपलब्ध हैं :

http://www.itforchange.net/Letter_Rajasthan_government_Laptop_purchase_feb2013

नीरू मल्होत्रा

09916893596

IT for Change

www.ITforChange.net